भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1786
उत्तर देने की तारीख-11/12/2024

शोध प्रकाशनों में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) का उपयोग

1786 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसंधान प्रकाशनों में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) के बढ़ते उपयोग से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार अनुसंधान में एआई उपयोग के लिए प्रकटीकरण मानदंड और एसओपी या नैतिक दिशा-निर्देश लागू करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार अनुसंधान प्रकाशनों में एआई के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए कोई एआई 'डिटेक्शन टूल' विकसित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में एक व्यापक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण पद्धति, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन और छात्र कल्याण को बढ़ावा देना जैसे फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक-सामाजिक कल्याण और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए ठोस नैतिक आधार शामिल हैं।

एनईपी 2020 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना सहित भारत में अनुसंधान के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार ने अनुसंधान और शिक्षा में संसाधनों का समान वित्तपोषण और लोकतंत्रीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से "अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन" (एएनआरएफ) की स्थापना की है।

इसके अलावा, एएनआरएफ पहल में सहायता करने के लिए, सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) को मंजूरी दी है। ओएनओएस में केंद्र या

राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के सभी विषयों के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के विशाल समुदाय को एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से शोध पत्रिकाओं तक पहुंच का विस्तार करना है।

अच्छे अकादमिक शोध अभ्यासों को सुनिश्चित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और साहित्यिक चोरी की रोकथाम) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है। यूजीसी द्वारा 28 अक्टूबर, 2020 को अच्छे अकादमिक शोध अभ्यासों पर एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ जारी किया गया है। यह दस्तावेज़ अनुसंधान जीवन चक्र के प्रत्येक चरण में संभावित खतरों और अच्छी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा, 7 नवंबर 2022 में अधिसूचित यूजीसी (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2022 में पीएचडी कार्यक्रम में नामांकित सभी छात्रों को कोर्सवर्क के हिस्से के रूप में "शोध और प्रकाशन नैतिकता" में एक पाठ्यक्रम पूरा करना होना है।

शिक्षा मंत्रालय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईसीटी) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन को भी कार्यान्वित करता है। एनएमईआईसीटी के तहत, "शोध शुद्धि" परियोजना के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पीडीएस (साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर) प्रदान किया जाता है। पीडीएस सॉफ्टवेयर में एआई द्वारा सृजित सामग्री की रिपोर्ट करने की क्षमता है।

*****